

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 742
दिनांक 04 दिसंबर 2025

भारत की परिष्करण और जैव ईंधन क्षमता का विस्तार

742. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

सुश्री कंगना रनौत:

श्री दिलेश्वर कामैत:

श्री मनोज तिवारी:

डॉ. मन्ना लाल रावत:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री दिलीप शङ्कीया:

क्या *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की भारत की परिष्करण क्षमता बढ़ाने और भावी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेट्रोकेमिकल और हरित ऊर्जा घटकों को एकीकृत करने हेतु क्या योजनाएँ हैं;

(ख) राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण के भीतर स्वच्छ विकल्प के रूप में जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और एलएनजी को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पहलें भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं को किस प्रकार सुदृढ़ करेंगी; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2047 तक अपेक्षित निवेश और रोजगार क्षमता कितनी है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) देश की वर्तमान कुल रिफाइनिंग क्षमता 258.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 309.5 एमएमटीपीए होने का अनुमान है। इसके साथ ही, चल रही और नियोजित समग्र रिफाइनरी परियोजनाओं के पूरा होने पर, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों का समग्र पेट्रोकेमिकल इंटेनसिटी इंडेक्स (पीआईआई) 4.1 से बढ़कर लगभग 9.3 होने का अनुमान है। सरकार ने

जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कार्यान्वित की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करना और इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फीडस्टॉक का दायरा बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण (पीएम जी-वन) योजना किफायती विमानन ईंधन (एसएएफ) समेत उन्नत बायोईंधन के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देने के लिए शुरू की गई है। संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) योजना शुरू की गई है, और बायोमास एकत्रीकरण को समर्थन देने और सीबीजी संयंत्रों को मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के लिए बीएएम (बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी) और डीपीआई (डायरेक्ट पाइपलाइन अवसंरचना) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2030 तक 5 एमएमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) शुरू किया गया है। सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए एलएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एलएनजी टर्मिनलों और एलएनजी स्टेशनों समेत एलएनजी अवसंरचना की स्थापना करना शामिल है।

(ग) जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन और एलएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन में परिवहन और सीमेंट, लोहा और स्टील जैसे दूसरे ज़रूरी, मुश्किल से कम होने वाले उद्योगों सहित सभी खास क्षेत्रों में उत्सर्जन को टालने में योगदान देने की क्षमता है। इन्हें अपनाने से समग्र उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में मदद मिल सकती है और यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव करने में सहायता करके राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाता है।

(घ) वर्ष 2047 तक ऐसी परियोजनाएं से होने वाले निवेश और सृजित होने वाले रोज़गार का अनुमान इस अवस्था पर नहीं लगाया जा सकता।
